सफल होने के लिए विफलता का स्वाद अवश्य चखना चाहिए ताकि यह पता चले कि अगली बार क्या नहीं करना है।- **एंथनीजे.डीएंजलो**

पोलमपोल भायो | गठबंधन मतलब अश्यो, आवो बाँटा राज | शिवसेना ने चायजे, महाराष्ट्र में ताज

सम्पादकीय

अमरीका यात्रा के मायने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज से शुरू हो रही पांच दिवसीय अमरीका यात्रा से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शुमार भारत और अमरीका के सम्बंध अब तक खट्टे-मीठे रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के साथ खड़ा रहने वाला भारत आज उस दौर से गुजर रहा है, जहां उसे किसी खेमे के साथ जुड़े रहने की जरूरत नहीं है। चार दशक पहले और आज की दुनिया में काफी बदलाव आ गया है। तब ताकत का मतलब सैन्य क्षमता से जोड़कर देखा जाता था तो आज ताकत का मतलब आर्थिक सम्पन्नता से जोड़कर देखा जाता है। समूची दुनिया ऐसे बाजार में बदल चुकी है जिस पर कब्जे की होड़ में बड़े-बड़े देश लगे हैं। ऐसे दौर में नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा खास मायने रखती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान, नेपाल व भूटान की यात्रा कर चुके मोदी की अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात पर देश ही नहीं, पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं।

समूची दुनिया ऐसे बाजार में बदल चुकी है जिस पर कब्जा करने की होड़ में बड़े-बड़े देश लगे हुए हैं। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा खास मायने रखती है।

पहले ही प्रयास में मंगल मिशन के सफल होने से भारत की साख बढ़ी है। ऐसे समय में मोदी की अमरीका यात्रा दोनों देशों को कितना नजदीक लाती है, यह देखने वाली बात होगी। भारत की चुनौतियां किसी से छिपी नहीं है। आतंकवाद से निपटना और देश को विकास के पथ पर सरपट दौड़ाना देश की दो बड़ी प्राथमिकताएं हैं। अमरीका इन दोनों प्राथमिकताओं को पूरा करने में कितना मददगार होता है, देशवासियों की नजर इस पर रहेगी। अमरीका हथियारों का बड़ा सौदागर हो सकता है लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति भी सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीका क्या उतनी मदद देगा जितनी हमारी अपेक्षा है? अमरीका बड़ी ताकत है देखने वाली बात ये होगी कि मदद के बदले वह हमसे क्या चाहता है? यह भी किसी से छिपा नहीं है कि किसी भी समझौते में अमरीका पहले अपना फायदा देखता है। दुनिया को वह एक बाजार के रूप में ही देखता है। पिछले सालों में अमरीका के साथ भारतीय सम्बंधों में सुधार आया है। लेकिन क्या भारत को उसके झंडे के नीचे खड़ा नजर आना चाहिए? सवाल अनेक हैं लेकिन इनके जवाबों के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। सप्ताह भर बाद पता चलेगा कि मोदी अमरीका पर अपना जादू चला पाए या नहीं? तभी इस बात का भी खुलासा होगा कि हमने क्या पाया और इसके बदले कहीं, कुछ खोना तो नहीं पड़ा?

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। - वाल्तेयर

बात-करामात

बाबू बहानेबाज

छोटे-बड़े बाबुओं का सरकारी लंच आधा घंटे का होता है लेकिन वह एक घंटे तक खिंच जाता है। जैसे 'लंच ब्रेक' होता है डेढ़ से दो लेकिन बाबू साहब सवा बजे से ही आंके-बांके होने लगते हैं और फिर सवा दो बजे तक सीट पर बिराजते हैं। यह हाल तो उन बाबुओं का है जिनकी गिनती वर्करों में होती है अब जरा निकम्मों का हाल सुनिए। अगर सुबह ग्यारह बजे भी उनकी सीट पर जाओ तो जवाब मिलता है कि चाय पीने गए हैं और फिर उनकी चाय ग्यारह से शाम चार बजे तक चलती है। कुछ बाबू अपनी कुर्सी पर कोट टांग कर गायब हो जाते हैं। पूछो तो चपरासी कहता है, यहीं आस-पास होंगे कोट तो यहीं है। कोई-कोई बाबू हमेशा 'खाना खाने गए हैं' की मुद्रा में रहते हैं। कभी किसी को पूछो तो पता चलता है कि बैंक गए हैं, अभी आते होंगे।

कभी-कभी कहा जाता है कि पड़ोस में कोई मर गया श्मशान गए हैं और बाबूजी सलमान खान की 'दबंग' देख रहे होते हैं। यह तो टुच्चे बाबुओं का हाल है। बड़े बाबू यानी सरकारी अफसरों के अंदाज निराले हैं। एक जनाब डेढ़ बजे लंच करने सरकारी कार से बंगले जाते हैं और चार बजे लौटते हैं मानो मेम साब ने टेप से चिपका दिया हो। एक साहब का चपरासी डेढ़ बजते ही उनके दफ्तर की सांकली बाहर से बंद कर देता है और साढ़े तीन बजे खोलता है जब तक साहब रात की खुमारी दिन में निकाल लेते हैं। एक हुजूर की मुंहलगी जब मन हो दफ्तर आ धमकती है और साहब 'मिटिंग' में व्यस्त हो जाते हैं। बाप रे बाप। कितने बहाने हैं। चाहो तो 'साहब के लंच समय का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करके' आप पीएचडी कर सकते हैं। अब सुना है कि अपने तेज तर्रार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के बाबुओं पर नकेल कसी है। हम तो उनसे गुजारिश करते हैं- भाई! एक नजर जरा राज्य की राजधानियों के छोट- बड़े बाबुओं पर भी डालो लेकिन कुछ बाबू ऐसे भी हैं जो बेचारे आते ही काम पर जुट जाते हैं और उन्हें घराळी का थमाया टिफिन खोलने की भी फुरसत नहीं मिलती लेकिन ऐसे लोगों की संख्या गिनती की है। दरअसल सारा मसला बड़े बाबू यानी अफसरों की काहिली का ही है। जब अफसर ही पस्त होता है तो छोटे बाबू को मस्त होने से किसी का मायबाप भी नहीं रोक सकता। अभी तो हिन्द का होटल राम भरोसे ही चल रहा है।

कुछ बाबू आते ही काम में जुट जाते हैं। उन्हें घराळी का थमाया टिफिन खोलने की भी फुरसत नहीं मिलती।

-राही

प्रत्यक्ष : निमंत्रण

महासमर 2227

अपने औरस पुत्र की बात मेरे मन में नहीं थी। फिर वह सुभद्रा का सबसे बड़ा पुत्र है, इसलिए हम परिवेदन जैसे पाप से भी बच जाते हैं।'

'जब इतना सोचा है तो यह भी सोचा होगा कि अभिमन्यु और उत्तरा की अवस्था अभी ब्रह्मचर्य की है। अभी उनकी विवाह की अवस्था नहीं आई है तो आर्य मर्यादा का उल्लंघन तो हम कर ही रहे हैं।' द्रौपदी ने कहा।

'यह आपातकाल है देवि। इसलिए इसे आपद्धर्म ही मानो।' अर्जुन ने कहा, 'युद्ध सिर पर है। अभी इन बच्चों की अवस्था युद्ध की भी नहीं है किंतु ये युद्ध करेंगे। तो ऐसे में यदि वे अपनी अवस्था से पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है।' अर्जुन को विदा कर द्रौपदी ने तत्काल ही अपनी दासी को भीम के पास दौड़ा दिया, 'जा, जा कर मध्यम पांडव से कह कि मैंने उन्हें स्मरण किया है। मैं तत्काल मिलना चाहती हूं। यदि वे न आए तो मैं उनके कक्ष की ओर आ रही हूं। फिर न कहें कि वे किसी मंत्रणा में व्यस्त हैं।'

दासी ने रानी की विकलता देखी तो मुस्कराना चाह कर भी नहीं मुस्कराई। उपप्लव्य में आज कल परिस्थितियां ही ऐसी थीं। एक ओर विवाह की धूम थी और दूसरी ओर युद्ध का वातावरण। पता नहीं युद्ध पहले होगा अथवा विवाह। भीम ने आने में देर नहीं की।'क्या बात है प्रिये! उसे द्रौपदी का आनन उल्लसित दिखाई नहीं पड़ रहा था।'मेरे मन में एक बात आई है।' द्रौपदी बोली, 'अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर संबंधियों और कुटुंबियों को तो आमंत्रित किया जाएगा न?''हां प्रिये! क्यों नहीं। बिना अतिथियों के भी कभी विवाह हुआ है क्या?'

'क्या इस बार भी राजसूय यज्ञ के अवसर के ही समान तुम लोग हस्तिनापुर से अपने शत्रुओं को आमंत्रित करोगे और उनकी प्रसन्नता के लिए मेरे पिता और भाइयों की अवमानना करोगे?'भीम गंभीर ही नहीं, कुछ चिंतित भी दिखाई दिया, 'तुम्हारी यह आशंका महत्त्वपूर्ण है।''क्या इस बार भी ऐसा ही होगा?' द्रौपदी ने कुछ आग्रहपूर्वक पूछा।

'कह नहीं सकता कि धर्मराज के मन में क्या है किंतु मेरा विचार है कि हम दुर्योधन से अपना भ्रातृत्व बहुत निभा चुके। वह हमारा भाई कभी नहीं बना, न ही बन सकता है। मुझे तो पितामह पर भी संदेह है कि वे कभी दुर्योधन का साथ छोड़ेंगे। जो हमारे नहीं हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपनों की अवज्ञा बहुत कर चुके।' उसने द्रौपदी की ओर देखा, 'मैं धर्मराज से आग्रह करूंगा कि वे जहां चाहें निमंत्रण भेजें किंतु अपने शत्रुओं को आमंत्रित न करें और अपने मित्रों की अवहेलना भी न करें।'

'सत्य कह रहे हो मध्यम पांडव?' 'युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। हम पंचालों की सहायता के बिना तो युद्ध कर ही नहीं सकते।' भीम ने कहा, 'अपने स्नेह अथवा संबंधों के कारण न सही, अपने स्वार्थ के कारण ही सही, हमें पंचालों को पूर्ण सम्मान देकर आग्रहपूर्वक निमंत्रित करना होगा। यह तो धर्मराज की विचित्र लीला है कि जो हमारा मस्तक काट लेना चाहता है, उसे तो वे आदरपूर्वक बुलाएंगे और जो हमारे लिए अपने प्राण देने को तत्पर बैठे हैं, उनकी ओर देखेंगे भी नहीं।' 'सत्य कह रहे हो मध्यम?' द्रौपदी ने दूसरी बार पूछा। 'सत्य कह रहा हूं।' भीम ने दृढ़ता से कहा, 'इस विवाह में हस्तिनापुरवालों के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः विवाह के निमंत्रण के छद्म में हम युद्ध-निमंत्रण भेज रहे हैं। हम वर-यात्रा की नहीं, सेना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

क्रमशः

- नरेन्द्र कोहली

स्पॉटलाइट

चुनौती : केन्द्र सरकार ने शुरू किया 'मेक इन इंडिया' अभियान

क्या पूरा हो पाएगा सपना

एक समय था जब सारी दुनिया के देश व्यापार करने के लिए भारत आने को लालायित रहते थे। उन्हें बुलाना या आमंत्रित नहीं करना होता था। वजह साफ थी। सभी को भारत से और भारत में व्यापार करने में अपने लिए लाभ नजर आता था। आज स्थिति एकदम बदली हुई है... उदारीकरण के बाद भी सेवा क्षेत्र का विस्तार तो बहुत हुआ पर रोजगार मूलक विकास आज भी एक सपना ही बना हुआ है। नई सरकार ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया है। पढ़िए, सरकार की इस कोशिश में कितना जोश है और कितना होश।

वैश्विक विनिर्माण में हिस्सेदारी

चीन	22.4	कोरिया	2.8	भारत	2.1	मेक्सिको	1.8
अमरीका	17.4	इटली	2.4	फ्रांस	2.0	स्पेन	1.4
जापान	9.7	रूस	2.3	इंग्लैण्ड	1.9		
जर्मनी	6.0	ब्राजील	2.2	इण्डोनेशिया	1.8		

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र संघ। आंकड़े प्रतिशत में

विनिर्माण का जीडीपी में हिस्सा

चीन	33	पाक	19	भारत	15	इंग्लैण्ड	11
इण्डोनेशिया	26	श्रीलंका	19	रूस	14	ऑस्ट्रेलिया	9
जापान	22	बांग्लादेश	19	अमरीका	13		
जर्मनी	20	द.अफ्रीका	16	ब्राजील	13		

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र संघ। आंकड़े प्रतिशत में

बढ़ेंगे रोजगार

अरुण मैरा, पूर्व सदस्य, योजना आयोग

देश के विनिर्माण सेक्टर पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी था। सर्विस सेक्टर तो हमारे देश में बहुत बढ़ गया है पर उसमें हमारे देश की बेरोजगारी का हल नहीं है। सर्विस सेक्टर का इससे अधिक विकास वर्तमान हालात में संभव नहीं है। सर्विस सेक्टर में आगे विकास के लिए मांग बढ़ानी होगी। यह मांग विनिर्माण सेक्टर में विकास के माध्यम से ही बढ़ सकती है। हमारे देश में जितनी बेरोजगारी है उसका हल विनिर्माण सेक्टर में ही है। पिछले बीस वर्षों से इस सेक्टर पर जितना ध्यान दिया जाना था उतना दिया नहीं गया। कुछ किया भी गया तो उसके वैसे परिणाम निकले नहीं।

भारत के व्यापार भुगतान को संतुलित करने के लिए भी विनिर्माण सेक्टर की जरूरत है। भारत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है। इसके लिए हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होता है। पर बदले में हमारे पास निर्यात करने के लिए बहुत कम वस्तुएं और सेवाएं हैं। सर्विस सेक्टर का स्वभाव ही होता है कि उसका उपभोग स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। उसका निर्यात नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए नाई या हेयर ड्रेसर अपनी सेवा का निर्यात नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जरूर निर्यात योग्य है पर उसकी भागीदारी पूरे सेवा क्षेत्र में लगभग 5-6 प्रतिशत ही है। इसलिए इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पर अगर हम सामान और वस्तुएं बनाएं, वह किसी भी सेक्टर में हो जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रोनिक, टैक्सटाइल सभी का निर्यात किया जा सकता है। इनको बेचने से जो भी विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी उसका उपयोग भुगतान संतुलन में किया जा सकता है।

विनिर्माण सेक्टर में बहुत सारे छोटे और मंझोले उद्योग भी आते हैं। रोजगार देने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। पर दुनिया में भारत के छोटे और मंझोले उद्योगों की उत्पादकता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। वे अन्य देशों की तुलना में टिक नहीं सकते। इसका कारण है प्रशासनिक मशीनरी की उलझी प्रक्रियाएं। इन उद्योगों के मालिकों का अधिकांश समय इन्हीं प्रशासनिक इंस्पेक्टरों और प्रक्रियाओं से निपटने में निकल जाता है। वे प्रतिस्पर्धी हो ही नहीं पाते। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस ओर इशारा भी किया है। इन उद्योगों की एक बड़ी समस्या क्रेडिट की होती है। बड़ी कंपनियों को तो बैंक ऋण दे देते हैं पर छोटे उद्योगों को नहीं देते। लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करने की बात कहते हैं। अब सरकार सही दिशा में जा रही है।

सही दिशा, समयानुकूल कदम

जी. रमेश, चेयरपर्सन, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी, आईआईएम बैंगलोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मेक इन इंडिया' अभियान अपनी नीति और रणनीति के स्तर पर काफी नायाब है। नीति के स्तर पर इसमें यह कोशिश की जा रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं रहे। सभी सेक्टरों जैसे कृषि, विनिर्माण, सॉफ्टवेयर तथा अन्य सेवा उद्योगों का साथ-साथ विकास हो। इसके साथ ही सरकार का फोकस सब्सिडी देने पर नहीं है। निवेश के लिए प्रधानमंत्री किसी उद्योग को कोई सब्सिडी देने की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि उनका जोर बेहतर और त्वरित शासन पर है। इसके लिए उन्होंने यह बात भी कही है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमें भारत की छवि बदलनी होगी। स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि आप आइए, आपका पैसा डूबेगा नहीं।

रणनीति के स्तर इसमें कई पहल देखी जा सकती हैं। एक तरफ कोशिश है कि भारत के लोग विनिर्माण के लिए भारत के बाहर नहीं जाएं तो दूसरी तरफ यह कोशिश है कि बाहर के लोग भारत आएं। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि बाहर के लोग ज्वांइट वेंचर की बजाए सीधे एफडीआई लेकर आएं। इसलिए वे वहां के लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। इसमें भी प्रधानमंत्री की रणनीति में अपनी ओर से सक्रियता साफ देखी जा सकती है। अभी तक यह होता था कि हम नीति बना लेते थे और उम्मीद करते थे कि निवेशक अपने आप आ जाएंगे। पर अब इसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वे स्वयं ही निवेशकों से बात करें। सिर्फ नीति बना लेने से ही संवाद नहीं हो जाता।

संवाद के लिए सबसे पहले हमें उनको अपने से जोड़ना होगा। 200-300 ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया में काफी बड़े निवेश को नियंत्रित करती हैं। मोदी सभी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा नूयी भी इन्हीं में एक हैं। यह एक नई बात है। अभी तक राज्य के स्तर पर चंद्रबाबू नायडू इस तरह के प्रयास किया करते थे। अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर के स्तर पर बात करें तो डिफेन्स, एयरोस्पेस, फॉर्मास्यूटिकल, बुनियादी संरचना और टूरिज्म आदि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हैं। एयरोस्पेस के लिए तो संभवतः बेंगलूरु में ही उद्योग स्थापित किया जाएगा।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि हम चीन का मॉडल अपना रहे हैं। चीन ने तो हर इंडस्ट्री के लिए अलग-अलग सब्सिडी देकर कंपनियों का बुला लिया है। वहां सब कुछ द्विपक्षीय स्तर पर होता है। नीति नहीं होती। द्विपक्षीय डीलिंग होती है। पर मोदी ने अभी तक जो कहा है उससे ऐसा लगता है वे किसी इंडस्ट्री विशेष को कोई विशेष सब्सिडी देने के मूड में नहीं हैं। वे सिर्फ बेहतर शासन की बात कर रहे हैं। यह ठीक भी है। किसी भी उद्योग के लिए शासन की लंबी-चौड़ी उलझाने वाली औपचारिकताओं की कीमत हमेशा उसके बदले में दी जाने वाली सब्सिडी से ज्यादा होती है।

अनेक लोग भारत में निवेश करना तो चाहते हैं पर वे कहते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने भारत में निवेश किया है उनके अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। यह जरूरी है कि हम भारत की छवि बदलें। भारत लोकतंत्र है। वहां कानून का शासन है यह तो सब मानते हैं पर उसके साथ ही दूसरी अन्य सरकारी अड़चनें भी हैं। इन्हें दूर करना होगा।

उद्योग के लिए शासन की लंबी-चौड़ी उलझाने वाली औपचारिकताओं की कीमत उसके बदले में दी जाने वाली सब्सिडी से हमेशा ज्यादा होती है।

चेन्नई और बेंगलूरु से सीखें

विनिर्माण उद्योग की जरूरत क्यों है इसको समझने के लिए हमें चैन्नई(तमिलनाडु) और बेंगलूरु (कर्नाटक) के विकास मॉडल को समझना होगा। चैन्नई में कृषि के साथ ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सभी को विकास में समुचित स्थान दिया गया है। जबकि बेंगलूरु में साफ्टवेयर इंडस्ट्री पर सारा जोर है। जब अमरीका में कुछ होता है या इस सेक्टर में मंदी आती है तो बेंगलूरु की पूरी अर्थव्यवस्था को झटका लगता है जबकि तमिलनाडु में एक सेक्टर की मंदी को दूसरा सेक्टर संतुलित कर देता है। पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहता है। चूंकि हम रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर नहीं कर सकते इसलिए मध्य में स्थित विनिर्माण सेक्टर रोजगार की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प साबित होता है। जब दुनिया के अनेक देश विनिर्माण सेक्टर के तेज विकास से उच्च विकास दर हासिल कर सकते हैं तो हम भी वैसा कर सकते हैं।

...सिर्फ बातें ही बातें

अरुण कुमार, प्रोफेसर, जेएनयू, नई दिल्ली

मेक इन इंडिया या इसके पहले भी जो दूसरे कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं उनमें मुझे दिखावा ज्यादा नजर आता है। उसमें रणनीति और स्पष्टता का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं नजर आ रही हैं। उदाहरण के लिए योजना आयोग खत्म कर दिया। पर योजना आयोग जो काम कर रहा था उसे अब कौन करेगा, यह कहीं स्पष्ट नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था काफी जटिल है। आज हालात ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत रोजगार देने वाला सेक्टर है कृषि क्षेत्र, पर उसमें मात्र 4 प्रतिशत निवेश आ रहा है। जबकि बड़े उद्योग कहे जाने वाले सेक्टर में 80 प्रतिशत निवेश हो रहा पर वह मात्र 6 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। शेष 44 प्रतिशत रोजगार छोटे और मंझोले उद्योगों में मिलता है पर उसमें मात्र 16 प्रतिशत निवेश हो रहा है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सब कुछ आयात करने की छूट मिल जाने के बाद छोटे और लघु उद्योगों को जो संरक्षण मिलता था वह सब खत्म हो गया है। जरूरत इस बात की थी कि सरकार इस क्षेत्र को संरक्षित करती। यह तय करती कि किस सेक्टर में कौन सा सामान बनेगा। इनकी क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन आदि की दूसरी समस्याओं का निपटारा करती। पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है। नतीजा सामने है।

चीनी माल ने इन छोटे उद्योगों के माल को बाजार से बेदखल कर दिया है। पर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। अब आप जर्मन कंपनी सीमेन्स को पावर प्लांट के लिए बुला लेंगे तो वह भेल को पीट ही देगी। क्योंकि उनके पास बेहतर टेक्नालॉजी है। पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। फिर हमारे देश में लोकतंत्र है जबकि चीन में तानाशाही है। प्रतिस्पर्धा में इन सब कारकों का भी असर होता है। चीन में भारी सब्सिडी मिलती है। इन सबको देखे बिना सबके लिए बाजार खोल देना, सबको भारत में निर्माण के लिए बुलाना कोई समझदारी नहीं है।

चीन में तानाशाही है, भारी सब्सिडी मिलती है। यह देखे बिना बाजार खोल देना, सबको भारत में निर्माण के लिए बुलाना कोई समझदारी नहीं है।

लेने होंगे कठोर फैसले

कुमार आनंद, अर्थशास्त्री,सीसीएस

मेक इन इंडिया अभियान में कई स्वागत योग्य पहलू शामिल हैं। इस अभियान में रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। एक वेबसाइट शुरू की गई जिसमें देशी तथा विदेशी कंपनियों की नीतिगत समस्याओं का समाधान और सवालों के जवाब 72 घंटें के भीतर उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

चूंकि इस अभियान में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़े सुधार की बात नहीं कही गई है इसलिए, लोक नीतियों से संबंधित सुधार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मोदी सरकार के छोटे से कार्यकाल पर यदि निगाह डाली जाए तो यह साबित होता है कि जुबानी दावे तो बहुत किए गए लेकिन जमीनी उपलब्धियों के नाम पर इनके पास गिनाने को बहुत कम चीजे हैं। यह जरूर है कि मोदी सरकार के आते ही नौकरशाहों के कार्य करने के घंटों में वृद्धि हुई है। लेकिन, सुशासन के नाम पर जितने कार्य हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित दिखाई देते हैं। विदेशी संस्थाएं विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश करने के भारत के आग्रह को गंभीरता से लें इसके लिए देश को अभी लंबा फासला तय करना पड़ेगा। मोदी भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।

व्यापार करने की सहूलियत, आर्थिक आजादी, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के आधार पर की जाने वाली वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहद खराब तो है ही, इसमें गिरावट भी आई है। 2006 में विश्व बैंक की व्यापार सुविधा रैंकिंग में भारत 116वें स्थान पर था जो 2014 में 134वें नंबर पर आ गया। इसी तरह नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता सूची में भारत शीर्ष के 70 देशों में भी नहीं है। मोदी को यह समझना पड़ेगा कि महज प्रशासनिक सुधार की सहायता से वह देश को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। कड़े फैसले लेने ही होंगे। ऐसे फैसले अलोकप्रिय होते हैं और मोदी सरकार फिलहाल तो उनसे बचते ही दिखती नजर आ रही है।

सुशासन के नाम पर जितने कार्य हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित दिखाई देते हैं। जरूरत है कड़े फैसले लेने की।

पाठक पीठ

ओछी अवसरवादिता

अपनी बात' के पाक्षिक स्तम्भ में आनंद जोशी का आलेख मीडिया व सरकार के दोगलेपन का खुलासा करता है। बड़ी घिन आती है ऐसी सोच पर जब देश के एक हिस्से में जहां चुनाव होने हैं, त्रासदी जनित पीड़ा लगती है जबकि दूसरे छोर का दर्द महसूस नहीं होता।ये कैसी अवसरवादिता है। **- श्याम गुप्ता,** जोधपुर

वाणी की महिमा

हाल ही 'स्पंदन' में वाणी पर पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी के सारगर्भित विचार पढ़े। इसकी विस्तृत व्याख्या में आपका कोई जवाब नहीं। इसमें जीवन दर्शन के बारे में अद्भुत जानकारी है। **- अशोक पानगड़िया,** जयपुर

आरक्षण का सच

पिछले दिनों द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के परिणाम में टीएसपी/ एसटी महिला मात्र18 फीसदी अंक पाकर भी शिक्षक बन गई। जो अभ्यर्थी खुद न्यूनतम 33 फीसदी अंक लाने में विफल रहे वे शिक्षक के रूप में नई पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे और कैसा परिणाम देंगे? **- कमल किशोर,** फुलेरा